



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 फरवरी, 2000/25 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-1)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जनवरी, 2000

संख्या कार्मिक (सचि० प्रशा०-1)ए(3)-4/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या कार्मिक (सचि० प्रशा०-1) ए (1)-3/78-III, तारीख 28 मई, 1996 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी (ग्रूफ रीडिंग) वर्ग-II, (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने के निम्ने निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश विधि अधिकारी (ग्रूफ रीडिंग) वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध-अ का संशोधन. —कामिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश विधि अधिकारी (प्रूफ रीडिंग) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति निगम, 1996 के उपाबन्ध 'अ' में,—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे अर्थात्:
“6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपये”

(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:
“18 से 38 वर्ष ।”

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिवृत्त हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्व ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये ह और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया हो या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हो ।

(2) अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:

(i) वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-03-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 6 वर्ष का उक्त संयुक्त नियमित सेवा काल हो, और शैक्षणिक योग्यता जैसी कि उपरोक्त स्तम्भ 7 (i) और (ii) में विहित की गई है,

- (ii) ऐसा न होने पर लिपिक/कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में संयुक्त रूप से 16 वर्षों का नियमित सेवा काल या 31-03-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 16 वर्षों का संयुक्त उपर्युक्त नियमित सेवाकाल हो, और शैक्षणिक योग्यता जैसी कि स्तर 7 (i) और (ii) में विहित की गई है,

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण पद पर तदर्थ नियुक्ति/भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित प्रक्रिया को अपनाते के पश्चात् की गई थी:

परन्तु यह कि जहां उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वागामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मेड पर्सनल परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसका अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इस प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(घ) स्तर 17 के मामले विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे अर्थात् :

“सेवा में, प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this Government Notification No. Per. (SAS-I) A(3) 4/99, dated 17-1-2000, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th January, 2000

No. Per. (SAS-I) A (3)-4/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend Law Officer (Proof Reading) Class-II, (Gazetted) Department of Personnel (Secretariat Administration) H. P. Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified *vide* notification No. Per. (SAS-I) A(I)-3/78-II dated 28th May, 1996 namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Law Officer (Proof Reading) Class-II (Gazetted) Department of Personnel (Secretariat Administration) H. P. Recruitment and Promotion (First Amendment), Rules, 2000.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure 'A' to the Law Officer (Proof Reading) Class-II (Gazetted) Department of Personnel (Secretariat Administration), H. P. Recruitment and Promotion Rules, 1996,—

(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640”.

(b) For the existing provisions against Column No. 6, the following shall be substituted, namely :—

“Between 18 to 38 years.”

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed

in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies:

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- (c) For the existing provisions against Column. No. 11, the following shall be substituted namely:—
- (i) By promotion from amongst Senior Assistants with 6 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service (rendered upto 31-3-1998) in the related field and Educational qualification as prescribed in Column No. 7(i) and (ii) above.
- (ii) Failing which by promotion from amongst Clerk/Junior Assistant/Senior Assistant with 16 years combined regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service (rendered upto 31-3-1998) in the related field and Educational Qualification prescribed in Column No. 7 (i) and (ii) above.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98) followed by regular service/appointment in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex-servicemen* recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex-servicemen* (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to the regular appointment/promotion/against such post shall

be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-98 as referred to above shall remain unchanged.

(d) For the existing provisions against Column No. 17, the following shall be substituted namely:—

“Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.”

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.